

हैबयिस कॉर्पस रटि मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षी मामले में कहा किलापता व्यक्तियों के मामलों को बंदी प्रत्यक्षीकरण (**Habeas Corpus**) याचिका के प्रावधान के तहत नहीं लाया जा सकता है।

प्रमुख बदि

- जस्टिस अरूप कुमार गोसवामी और जस्टिस एन.के. चद्रवंशी ने ऐसे मामलों के संदर्भ में कहा कि 'लापता व्यक्तियों के मामले भारतीय दंड संहति (आईपीसी) के नयिमति प्रावधानों के तहत दर्ज़ कयि जाने हैं और संबंधति पुलसि अधिकारी आपराधिक प्रक्रयिा संहति के तहत नरिधारति तरीके से इसकी जाँच करने के लयि बाध्य हैं।'
- उच्च न्यायालय ने कहा कि जो चीज सुसंगत रहती है वह यह है कि 'अवैध नरिोध' का आधार स्थापति करना और इस तरह की कसिी भी 'अवैध हरिसत' के बारे में एक मज़बूत संदेह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्थानांतरति करने के लयि एक शर्त है और संवैधानिक न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर वचिार नहीं करेगे, जहाँ 'अवैध हरिसत' के बारे में संदेह का कोई आरोप नहीं है।
- यूनयिन ऑफ इंडयिा बनाम युमनाम आनंद एम और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने नरिणय में कहा है कि 'संवधान के अनुच्छेद 21 में यह घोषति है कि कानून द्वारा स्थापति प्रक्रयिा के अनुसार कसिी भी व्यक्ता को जीवन और स्वतंत्रता से वंचति नहीं कयिा जाएगा। इसके अलावा, अत्यधिक तत्परता के साथ अवैध हरिसत के प्रश्न की जाँच करने के लयि एक मशीनरी की नश्चति रूप से आवश्यकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रटि इस प्रकृता का एक उपकरण है।'
- गौरतलब है कि संवधान के अनुच्छेद 32 में वर्णति संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत 5 रटि- बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतषिध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पृच्छा का उल्लेख है।